

आपदा, बेरोजगारी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉ. अनिल कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, श्री बजरंग पी. जी.

कॉलेज, दादर आश्रम, सिकंदरपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश

ईमेल- anil.bhu06@gmail.com

कोरोना आपदा

मानव जगत ने कई आपदाओं को देखा, झेला और फिर आगे बढ़ा है। एक ऐसी ही आपदा मानव समुदाय के समक्ष कोरोना वायरस (कोविड-19) के रूप में है। चीन के बुहान शहर से शुरू होकर धीरे-धीरे कोरोना वायरस का प्रकोप भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में फैल गया। कोरोना वायरस के प्रकोप से देश को बचाने हेतु मोदी सरकार ने मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की। कोरोना से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखी जा रही थी परन्तु यह आपदा ने इस स्थिति को और दयनीय बना दिया।

बेरोजगारी

जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो पर उसे कार्य न मिले तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं।

ऐच्छिक बेरोजगार-

ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते हैं या प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं करना चाहते हैं उन्हें ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं।

अनैच्छिक बेरोजगार-

जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार है और जिसे कार्य न मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं।

अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की सही स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी ही होती है जिसका अध्ययन किया जाता है।

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कार्य तो कर रहा है परन्तु राष्ट्रीय आय अर्थात् सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है या राष्ट्रीय आय में उसका योगदान शून्य है तो ऐसे व्यक्ति को भी बेरोजगार ही माना जाएगा।

अर्थव्यवस्था में वे सभी लोग जो कार्य करना चाहते हैं यदि उन्हें चालू बराबर मजदूरी पर कार्य मिल जाए तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी।

श्रम शक्ति-

किसी भी देश की श्रम शक्ति से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों से है जो 15-65 आयु वर्ग के हैं, जो रोजगार में हैं तथा वे भी जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

श्रम शक्ति= (रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या)

बेरोजगारी की दर= (बेरोजगारों की संख्या/श्रम शक्ति) ×100

आपदा के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की स्थिति

इस आपदा से देश के लोगों को बचाने हेतु भारत सरकार ने मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की। जिसके फलस्वरूप देश के अधिकांश उद्योग धंधों को बंद करना पड़ा, ट्रेन व यातायात को बंद करना पड़ा, अन्य संस्थानों को भी बंद करना पड़ा। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा

था। इसके प्रकोप से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी था और इसके लिए लॉकडाउन ही बेहतर उपाय रहा।

लॉकडाउन से मानव जगत को बहुत हद तक बचा लिया गया परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और बद से बदतर हो गयी।

लॉकडाउन लगने से एक तरफ जहां हम लोग कोरोना वायरस के प्रकोप से मानव जगत को बचाने का प्रयास किए, वहीं दूसरी ओर उत्पादन कार्य, ट्रेन, यातायात को बंद करने के फलस्वरूप देश में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ा। उद्योग धंधों को बंद करने से उस में कार्यरत मजदूरों को हटाना पड़ा क्योंकि कोई भी कंपनी बैठाकर मजदूरों को वेतन नहीं देगा। जिसके फलस्वरूप देश में बहुत व्यापक स्तर पर लोग बेरोजगार हुए। धीरे-धीरे कालांतर में लॉकडाउन हटा और सभी उद्योग धंधे, यातायात शुरू किया गया लेकिन दुर्भाग्यवश 2021 में भी कोरोना वायरस का दूसरा चरण बहुत तेजी से फैला। जिसके फलस्वरूप एक बार पुनः देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गयी।

इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा चरण आम जनता को पुनः बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया। कोरोना वायरस के प्रकोप से हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जहां एक ओर अर्थव्यवस्था में मंदी का असर दिख रहा था तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के कारण उद्योग धंधों और यातायात को पुनः बंद करना पड़ा। उद्योग धंधों के बंद होने के कारण उत्पादन गिरा, निवेश गिरा, मजदूरों को हटाना पड़ा। जिससे व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ा।

मुम्बई का एक थिंक टैंक 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी' (CMIE) देश में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े एकत्र करता है। इसके अनुसार मार्च, 2021 में देश में बेरोजगारी की दर 6.5% था, जोकि बढ़कर अप्रैल,

2021 में 8% हो गया। कोविड प्रतिबंधों, आर्थिक गतिविधियों को रोकने से अर्थात् लॉकडाउन के वजह से केवल अप्रैल, 2021 में 70 लाख लोगों के रोजगार छिन गए। सीएमआईई के अनुसार मई, 2021 में बेरोजगारी की दर 8% से बढ़कर 12% हो गई थी, जिसके फलस्वरूप लगभग एक करोड़ लोग बेरोजगार हो गए।

जून, 2021 में धीरे-धीरे राज्यों ने अनलॉक करना शुरू किया। जिससे उद्योग धंधे, यातायात, आर्थिक गतिविधियां शुरू हुईं और इसके फलस्वरूप बेरोजगारी की दर जून, 2021 में घटकर वापस 9% पर आ गई थी।

भारत सरकार ने इस आपदा के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु समय-समय पर राहत पैकेजों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने आपदा के समय मार्च 2020 में 1.7 ट्रिलियन रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। पुनः नवम्बर 2020 में 2.65 लाख करोड़ रुपए की व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की।

इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था इस आपदा के दुष्प्रभाव से बाहर निकल रही है और निवेश, उत्पादन और राष्ट्रीय आय बढ़ रही है साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। CMIE ने जुलाई 2022 में बेरोजगारी पर अपना रिपोर्ट पेश की। जुलाई 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 6.8% रही साथ ही साथ यह भी कहा कि आने वाले समय में देश में और बेरोजगारी की दर घटेगी।

अतः निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कोरोना वायरस भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय जनमानस को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। इसके

कारण राष्ट्रीय आय नीचे गिरा, बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ी। लेकिन अर्थव्यवस्था के अनलॉक हो जाने के कारण और विभिन्न राहत पैकेज देने के कारण धीरे-धीरे सभी उद्योग धंधे, यातायात और अन्य संस्थानों को खोल दिया गया, उत्पादन कार्य, निवेश किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति तीव्र गति से सुधर रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ा है, बेरोजगारी कम हो रही है और देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

सन्दर्भ-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था (2015). दत्त एवं सुन्दरम, एस. चन्द.
2. भारतीय अर्थव्यवस्था (2016). पुरी एवं मिश्र, हिमालय पब्लिशिंग हाउस.
3. भारतीय अर्थव्यवस्था- सर्वेक्षण तथा विश्लेषण (2019). एस. के. लाल व एस. एन. लाल, शिवम पब्लिशर्स. इलाहाबाद.
4. भारतीय अर्थव्यवस्था (2019). प्रतियोगिता दर्पण. आगरा.
5. अमर उजाला- दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी.
6. हिन्दुस्तान- दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी.
7. इंटरनेट.

.....